**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय**

**रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 4692**

**28 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**डीआरडीओ परियोजनाओं में देरी**

**4692. श्री जिया उर रहमान:**

**श्रीमती संजना जाटव:**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि देश की प्रमुख रक्षा अनुसंधान एजेंसी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) प्रणालीगत समस्याओं से ग्रस्त हो गयी है, जिसके परिणामस्वरूप लगातार अत्यधिक देरी और लागत में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए/प्रस्तावित उपचारात्मक कदमों का ब्यौरा दें;

(ग) क्या डीआरडीओ ने बहुत अधिक परियोजनाओं को लेकर अपना फोकस रक्षा अनुसंधान से दूर कर दिया है और अन्य क्षेत्रों में अपना विस्तार कर लिया है; तथा

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें?

**उत्तर**

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ)**

(क) से (घ): अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास में शामिल जटिलताओं और गहन अनिश्चितताओं को ध्यान में रखकर, किसी भी रक्षा अनुसंधान और विकास परियोजना को पूरा करने के लिए सटीक समय और लागत का अनुमान लगाना एक निरन्तर प्रक्रिया है। अनुसंधान के क्षेत्रों की पहचान दीर्घकालिक प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य योजना (एलटीटीपीपी), दीर्घकालिक एकीकृत परिप्रेक्ष्य योजना (एलटीआईपीपी), डीआरडीओ पंचवर्षीय योजना (एफवाईपी), विजन दस्तावेज और रोडमैप के आधार पर की जाती है।

इसके साथ ही निम्नलिखित नई पहलें शुरू की गई हैं:-

- डीआरडीओ द्वारा प्रौद्योगिकी विकास के विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान की गई है जिन्हें उद्योगों को स्थानांतरित किया गया है और डीआरडीओ द्वारा उन क्षेत्रों में परियोजनाएं नहीं की जा रही हैं।

- मिशन मोड परियोजनाओं को रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) या रक्षा प्रापण बोर्ड (डीपीबी) या सर्विसेज प्रापण बोर्ड (एसपीबी) द्वारा आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) के बाद ही लिया जाता है।
- डीआरडीओ भारतीय रक्षा उद्योग का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है, और इस बात पर जोर देता है कि निजी क्षेत्र द्वारा किए गए प्रयासों की पुनरावृत्ति नहीं की जा रही है। 'जो उद्योग कर सकता है, डीआरडीओ नहीं उसे करेगा', मिशन के साथ डीआरडीओ मुख्य रूप से महत्वपूर्ण और उन्नत प्रौद्योगिकियों के डिजाइन और विकास के साथ-साथ जटिल प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिन्हें उद्योग उच्च जोखिम या उच्च लागत के कारण नहीं करते हैं।
- डीआरडीओ के पास 10 वर्षों का रोडमैप है जिसकी समीक्षा और संशोधन कर यह सुनिश्चित किया गया है कि परियोजनाओं को फोकस क्षेत्रों से लिया गया है और वे उपलब्ध संसाधनों पर आधारित है।
- डीआरडीओ-उद्योग-अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र (डीआईए-सीओई) रक्षा अनुप्रयोगों से संबंधित महत्वपूर्ण और भविष्य के क्षेत्रों में निर्देशित अनुसंधान करने के लिए डीआरडीओ प्रयोगशालाओं और उद्योग को सहायता प्रदान कर रहे हैं।
- डीआरडीओ ने अपने नीतिगत दस्तावेजों में अपनी कार्यप्रणाली और प्रक्रियाओं में व्यापक सुधार किया है जैसे वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन, प्रापण मैनुअल और परियोजना निर्माण और प्रबंधन के लिए निर्देश। इसे संशोधित किया गया है जिससे इसके विकेन्द्रीकरण के साथ-साथ तीव्र निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके। इससे संगठन की समग्र दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार और वृद्धि होती है।

*****